

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 180
21.06.2019 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन

180. श्री जी. एम. सिद्देश्वरा :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने वैश्विक एजेंसियों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावेडकर)

(क) और (ख) भारत सरकार ने 'जलवायु परिवर्तन और भारत : एक 4x4 आकलन-2030 दशक के लिए एक खण्डीय और क्षेत्रीय विश्लेषण' शीर्षक से अध्ययन करवाया है जिसमें भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों नामतः हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर भारतीय अर्थव्यवस्था के चार मुख्य क्षेत्रों नामतः कृषि, जल, वन और मानव स्वास्थ्य पर 2030 में पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है।

(ग) और (घ) पेरिस करार के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2021-2030 के लिए आठ (8) लक्ष्यों को शामिल करते हुए अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रस्तुत किए हैं जिनमें (i) वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तरों से 33 से 35 प्रतिशत तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन सघनता को कम करना, (ii) वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत संस्थापित क्षमता को प्राप्त करना, (iii) वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से CO₂ के समकक्ष 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना शामिल है। अन्य लक्ष्य, वहनीय जीवनशैली; जलवायु अनुकूल वृद्धि पथ; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन; जलवायु परिवर्तन वित्त और क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं।
